ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS AND SUPPLEMENTARY QUESTIONS AND ANSWERS THEREON

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF JAL SHAKTI

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION

RAJYA SABHA

STARRED QUESTION NO. *1

ANSWERED ON 03.02.2025

'NAMAMI GODAVARI' RIVER INITIATIVE

*1 DR. AJEET MADHAVRAO GOPCHADE

Will the Minister of JAL SHAKTI be pleased to state:

(a) actions taken by Government in collaboration with State Government to assess the irrigation needs in the Marathwada region of Maharashtra, which is experiencing water shortages that hinder agricultural growth;

(b) whether Government has received representation for the 'Namami Godavari' river cleaning initiative similar to 'Namami Gange', the measures initiated thereon; and

(c) whether the Central Government, in conjunction with the State Government is planning to dispatch a team of experts to Marathwada to formulate a strategy for tackling the water scarcity problem, if not, the reasons therefor, if so, the steps which will be taken thereon?

ANSWER

THE MINISTER OF JAL SHAKTI

(SHRI C R PAATIL)

(a) to (c) : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (c) OF STARRED QUESTION NO. *1 TO BE ANSWERED ON 03.02.2025 IN RAJYA SABHA REGARDING "'NAMAMI GODAVARI' RIVER INITIATIVE"

(a) Water, being State subject, water resources projects are planned, funded, executed and maintained by the State Governments themselves as per their own resources and priority. In order to supplement their efforts, Government of India provides technical and financial assistance to State Governments to encourage sustainable development and efficient management of water resources under various ongoing schemes. Government of Maharashtra has informed that ultimate irrigation potential of Marathwada region is 19.50 lakh hectare, out of which 16.80 lakh hectare has been created through 1,270 completed and ongoing projects.

Government of India has included 4 major and medium projects viz. Lower Dudhna Project, Nandur Madhmeshwar Phase-II Project, Upper Kundalika Project and Upper Penganga Project, benefitting Marathwada region under Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP) and Command Area Development and Water Management (CAD&WM) components of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna (PMKSY). 1.09 lakh hectare irrigation potential has been created and 52.15 thousand hectare cultivable command area has been developed through these projects till December, 2024.

Further, a Special Package scheme for completion of irrigation projects to address agrarian distress in Vidarbha and Marathwada and other chronically drought prone areas of rest of Maharashtra has also been approved by Government of India in July, 2018. 17 surface minor irrigation projects of Marathwada region have been included under this scheme. 6,183 hectare irrigation potential has been developed through these minor irrigation projects till December, 2024.

In addition, National Water Development Agency under this Ministry has prepared pre-feasibility report of three intra-State river interlinking projects benefitting Marathwada region namely Wainganga–Manjra valley link project, Nar–Par–Girna valley link project and Upper Krishna – Bhima (system of six links). Though, first two intra-State river interlinking projects have not been found techno-economically feasible.

(b) It is the primary responsibility of States/Union Territories (UTs) and Urban Local Bodies to ensure required treatment of sewage and industrial effluents to the prescribed norms before discharging into the rivers and other water bodies.

The Govt. of India has been supplementing efforts of the States/UTs by providing financial and technical assistance for abatement of pollution in rivers/tributaries in Ganga basin through the Central Sector Scheme of Namami Gange Program, and the Centrally Sponsored Scheme of National River Conservation Plan for other rivers in the country. The State/UT Governments may prepare proposals for abatement of pollution in the rivers for consideration under the above schemes.

The representation received related to Namami Godavari has been forwarded to State of Maharashtra and Telangana for taking cognizance and suitable action.

(c) No. Government of India has already approved a special package to address agrarian distress in Vidarbha and Marathwada and other chronically drought prone areas of rest of Maharashtra. Further, to address the issue of development of irrigation in water scarce drought prone areas in India, special provisions have been made in criteria for selection of projects and central funding ratio under PMKSY-AIBP. If a project has more than 50% command in drought prone area, 50% advance stage criteria has been relaxed and the project can be included since beginning of the construction with enhance funding ratio of 60 (Centre): 40 (State) in the proportion of command area falling in drought prone area.

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *1

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

'नमामि गोदावरी' नदी सफाई पहल

1. डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र, जहां पानी की कमी के कारण कृषि विकास में बाधा आ रही है, में सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार को 'नमामि गंगे' के समान 'नमामि गोदावरी' नदी सफाई पहल के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो इस संबंध में किन उपायों की शुरूआत की गई है; और

(ग) क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ मिलकर, जल की कमी की समस्या से निपटने के लिए कार्यनीति तैयार करने हेतु विशेषज्ञों की एक टीम मराठवाड़ा भेजने की योजना बना रही है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाएंगे?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

"नमामि गोदावरी' नदी सफाई पहल" विषय पर दिनांक 03 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न *1 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): जल, जो कि राज्य का विषय है इसलिए जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, उनका वित्तपोषण, कार्यान्वयन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा स्वयं के संसाधनों और प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार, राज्य सरकार के प्रयासों में मदद देने के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जल संसाधनों के सतत विकास और कुशल प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

महाराष्ट्र सरकार ने जानकारी दी है कि मराठवाड़ा क्षेत्र की चरम सिंचाई क्षमता 19.50 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 16.80 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता को 1,270 पूरी की गई और चल रही परियोजनाओं के माध्यम से सृजित किया गया है।

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) घटकों के अंतर्गत मराठवाड़ा क्षेत्र को लाभान्वित करते हुए 4 वृहद और मध्यम परियोजनाओं अर्थात लोवर दुधाना परियोजना, नांदूर मधमेश्वर चरण-II परियोजना, अपर कुंडलिका परियोजना और अपर पैनगंगा परियोजना को शामिल किया है। इन परियोजनाओं के माध्यम से दिसंबर 2024 तक, 1.09 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है और 52.15 हजार हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र को विकसित किया गया है।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा विदर्भ और मराठवाड़ा सहित महाराष्ट्र के सूखा ग्रस्त शेष क्षेत्रों में कृषि संकट के समाधान हेतु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक विशेष पैकेज योजना को जुलाई 2018 में मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के अंतर्गत मराठवाड़ा क्षेत्र की 17 सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया गया है। दिसंबर 2024 तक, इन लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 6,183 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की गई है।

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा मराठवाड़ा क्षेत्र को लाभान्वित करने वाली नदियों को आपस में जोडने वाली तीन अंतरा राज्यीय परियोजनाओं नामत: - वैनगंगा-मंजरा नदी लिकं परियोजना, नार-पार-गिरणा नदी लिंक परियोजना और ऊपरी कृष्णा - भीमा (छह लिंकों की प्रणाली) की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। हालांकि, पहले वाली दो अंतरा राज्यीय नदी लिंक परियोजनाओं को प्रौद्योगिक-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

(ख): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों की यह प्राथमिक दायित्व है कि सीवेज और औद्योगिक बहि:स्रावों को नदियों और अन्य जल निकायों में छोड़े जाने से पहले इन बहि:स्रावों का अपेक्षित शोधन सुनिश्चित करें।

भारत सरकार द्वारा गंगा बेसिन की नदियों/सहायक नदियों में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना - नमामि गंगे कार्यक्रम और देश की अन्य नदियों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए मदद की जा रही है। उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें नदियों में प्रदूषण कम करने के संबंध में अपने प्रस्ताव तैयार कर सकती है।

नमामी गोदावरी से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदनों को महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य के संज्ञान में लाने और उचित कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया गया है।

(ग): जी नहीं। भारत सरकार ने विदर्भ और मराठवाड़ा सहित लंबें समय से चले आ रहे महाराष्ट्र के अन्य सूखा ग्रस्त शेष क्षेत्रों में कृषि संकट के समाधान के लिए पहले ही एक विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, भारत में जल संकट से जूझ रहे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई विकास मामलों के समाधान के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत चुनी गई परियोजनाओं और केंद्रीय वित्त पोषण अनुपात संबंधी मानदंडों के विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी परियोजना के सूखा संभावित क्षेत्र में 50% से अधिक कमान है तो उन्हें सूखा संभावित क्षेत्र के कमान के अनुपात में 60 (केंद्र): 40 (राज्य) के बढ़े हुए वित्त पोषण अनुपात के साथ 50% तक अग्रिम चरण के मानदंडों में छूट दी गई है जिसे परियोजना के निर्माण की शुरुआत से ही शामिल किया जा सकता है।

*****

डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः माननीय उपसभापति महोदय, परम पूज्य श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की पावन भूमि सचखंड हुजूर साहिब नांदेड़ है, जहां गोदावरी नदी केंद्रीय बिंदु है। यहाँ लाखों यात्री और श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं, लेकिन प्रदूषित जल की वजह से लाखों यात्रियों, नागरिकों, माताओं, बहनों और श्रद्धालुओं के लिए आरोग्य की समस्या उत्पन्न हो रही है और गोदावरी नदी के किनारे बसे शहरों में प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार गोदावरी नदी के प्रदूषण को साफ करने के लिए अधिक धनराशि आवंटित करेगी? क्योंकि वर्तमान में उपलब्ध राशि बहुत कम है, जिससे यह गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त नहीं हो सकती है, इसलिए क्या इस पर कोई विचार किया जा रहा है? ...(**व्यवधान**)...

श्री सी. आर. पाटिलः माननीय उपसभापति महोदय, सभी राज्यों और संघशासित राज्यों के द्वारा शहरों में होने वाला सीवेज ...(**व्यवधान**)... और इंडस्ट्री से आने वाले ...(**व्यवधान**)... पॉल्युटिड वेस्ट को पहले STP में ट्रीट करते हैं। ...(**व्यवधान**)... उसके बाद, उसे प्रोसेस करने के बाद ही नदी में डालने की व्यवस्था करनी है। "नमामि गंगे योजना" में जो नदियां आती हैं, उन सभी को केंद्र सरकार द्वारा टेक्नीकल सहायता दी जाती है। इसके साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है। माननीय मैम्बर ने गोदावरी नदी के लिए यहाँ पर जो प्रश्न उठाया है, उसके लिए हमें यहाँ पर जितने भी प्रयोजन प्राप्त हुए हैं ...(**व्यवधान**)... हमने वे सभी महाराष्ट्र सरकार और तेलंगाना सरकार को भेज दिए हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Second supplementary? ...(*Interruptions*)...

डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः उपसभापति जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए किसी विशेष जल संरक्षण योजना या परियोजना के बारे में सोच रही है? क्योंकि मराठवाड़ा क्षेत्र में जल संकट एक बहुत भीषण समस्या है, इसलिए क्या भारत सरकार इससे निपटने के लिए मराठवाड़ा के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक जल प्रबंधन नियोजन नीति पर कुछ विचार कर रही है?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is Question Hour. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Derekji, nothing is going on record. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... माननीय मंत्री जी, आप जवाब दे दीजिए। माननीय सभापति महोदय ने रूल 267 ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, I am not entertaining it. Please. ...(*Interruptions*)...

श्री सी. आर. पाटिलः माननीय उपसभापति महोदय, मराठवाड़ा में कुल चार बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाएं हैं। ...(**व्यवधान**)... उनमें से एक योजना पूर्ण हुई है। इसके अंदर 65,226 हैक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा। इसके अंदर कुल विकसित क्षेत्र 52,147 हैक्टेयर है। अभी तक उनको

कुल केंद्रीय सहायता के रूप में 162 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। पीएमकेएसवाई के द्वारा सूखा क्षेत्र के अंदर अनेक कार्यों और परियोजनाओं के द्वारा इन्हें बहाल करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कोशिश जारी है।

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

श्री उपसभापतिः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय डा. सिकंदर कुमार जी, आप अपना पहला सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछिए।

DR. SIKANDER KUMAR: Thank you, Sir, for giving me the opportunity. With your permission, I would like to know from the Minister whether the Government has any plan in near future to start cleaning drive in main rivers of the country. If yes, then, details thereof.

श्री सी.आर.पाटिलः माननीय उपसभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अनेक योजनाओं द्वारा नदी की सफाई, नदी की ड्रेज़िंग करने के काम करा रहे हैं। "नमामि गंगे योजना" भी इसी के अंदर आती है। इसके अंदर जो दो छोटी नदियां हैं और उनके साथ जो छह बड़ी नदियाँ हैं, उन पर काम हो रहा है। यदि किसी पर्टिकुलर नदी की बात करते हैं, तो मैं उस पर जवाब पक्का दूंगा, लेकिन मैं जनरल-वे में बता सकता हूं कि सभी नदियों की ड्रेज़िंग की जाती है। उनकी सफाई करने की ये सभी योजनाएं चल रही हैं और इनके अंदर आपको एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देखने को मिल रहा है।

श्री उपसभापति : क्वेश्चन नम्बर 2 . डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।